पटना के उच्च न्यायालय में

2008 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3982

निर्णय लियाः 09.04.2008

याचिकाकर्ताओंः **सुधीर कुमार ओझा**

बनाम

उत्तरदाताः बिहार राज्य और अन्य

न्यायालय शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम 2007-न्यायालय शुल्क में वृद्धि के विरोध में राज्य भर के वकील काम से विरत रहे हैं-- महाधिवक्ता का कहना है कि अदालत शुल्क में वृद्धि की समीक्षा मंत्रियों और अधिवक्ताओं की एक समिति द्वारा की जा रही है जो चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी-महाधिवक्ता आगे कहते हैं कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, अगर इस बीच, न्यायालयों[के साथ स्वीकार किया जाता है जो न्यायालय शुल्क] में दाखिल न्यायालय शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2007 से पहले लागू था। के है-न्यायालय शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम 2007 के लागू होने से पहले न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय में दाखिल स्वीकृत स्वीकार करने का आदेश दिया जाता है।) इस इस न्यायालय के किसी भी अगले आदेश के अधीन, घाटे वाले न्यायालय शुल्क के साथ स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

पटना के उच्च न्यायालय में

2008 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3982

निर्णय लियाः 09.04.2008

याचिकाकर्ताओंः **सुधीर कुमार ओझा**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य और अन्य**

माननीय न्यायाधीश/गणपूर्ति:

सी.के. प्रसाद, ए.सी.जे., बारीन घोष और जयनंदन सिंह, न्यायमूर्तिगण

निर्णय

सी.के. प्रसाद, एसीजे, बारीन घोष और जयनंदन सिंह, न्यायमूर्तिगण

1. राज्य भर के वकील न्यायालय शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा न्यायालय शुल्क में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। वे इस न्यायालय सहित सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के समक्ष अपने पेशेवर काम से दूर रह रहे हैं। इससे उनकी कार्यप्रणाली लगभग ठप हो गई है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उच्च न्यायालय के वकीलों की समन्वय समिति भी उपस्थित होती है। श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य के व्यवहार न्यायालयों के विभिन्न बार संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. हमने मौजूदा स्थिति के बारे में बार के सदस्यों को अपनी चिंता व्यक्त की। हमें यह दर्ज करते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

4. विद्वान महाधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय शुल्क में वृद्धि की समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह द्वारा की जा रही है जिसमें व्यवहार न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के वकीलों के संघों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हमारे सुझाव पर, उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि आमंत्रित वकीलों की संख्या 15 होगी और वास्तव में, उन्होंने अनुरोध किया है कि नाम उच्च न्यायालय के वकीलों की समन्वय समिति द्वारा सुझाए जाएं, जो हमें बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए राज्य के विभिन्न बार संघों द्वारा अधिकृत किया गया है।

5. सुझाए गए नाम इस प्रकार हैंः

1. अध्यक्ष, बेतिया व्यवहार न्यायालय बार संघ।

2. महासचिव, सीवान व्यवहार न्यायालय बार संघ।

3. महासचिव, पूर्णिया व्यवहार न्यायालय बार संघ।

4. अध्यक्ष, गया व्यवहार न्यायालय बार संघ।

5. अध्यक्ष, आरा व्यवहार न्यायालय बार संघ।

6. महासचिव, मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय बार संघ।

7. अध्यक्ष, पटना व्यवहार न्यायालय बार संघ।

8. श्री एस. एन. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

9. श्री राणा प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

10. श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

11. श्री योगेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

12. श्री बसंत कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

13. बालेश्वर शर्मा, सदस्य, बिहार बार परिषद।

14. श्री पी. के. झा, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

15. श्री राजीव रॉय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय।

6. विद्वान महाधिवक्ता का कहना है कि समिति चार सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसे न्यायालय में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

7. प्रश्न के उत्तर में, महाधिवक्ता आगे कहते हैं कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, यदि इस बीच, अदालतों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों में दलीलें आदि दायर करने को अदालत शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2007 के लागू होने से पहले अदालत शुल्क के साथ स्वीकार किया जाता है, जिसे मामले के परिणाम के अधीन, घाटे वाली अदालत शुल्क के साथ स्वीकृति के रूप में माना जाता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री योगेश चंद्र वर्मा, श्री राणा प्रताप सिंह, श्री उमा कांत शुक्ला, श्री बसंत कुमार चौधरी, श्री मनन कुमार मिश्रा, श्री पी. के. झा, श्री बिनय कांत मणि त्रिपाठी और अन्य सभी वकील हमें आश्वासन देते हैं कि राज्य भर के कानूनी बिरादरी के सदस्य कल यानी 10 अप्रैल, 2008 से अपना पेशेवर काम फिर से शुरू करेंगे।

9. हमें उपरोक्त प्रस्तुतियाँ दर्ज करने में खुशी हो रही है।

जो कुछ अभिलिखित किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय शुल्क (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2007 के लागू होने से पहले न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों में अभिवचनों आदि को स्वीकार किया जाए और अदालत शुल्क के साथ स्वीकार

किया जाए, जिसे इस न्यायालय द्वारा किसी भी आगे के आदेश के अधीन, घाटे वाले अदालत शुल्क के साथ स्वीकृति के रूप में माना जाए।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार मंत्रियों के समूह की अनुशंसा के आलोक में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

11. विद्वान महाधिवक्ता ने हमें सूचित किया है कि मंत्री समूह की बैठक कल यानी 10 अप्रैल, 2008 को दोपहर 2 बजे राज्य के माननीय उप-मुख्यमंत्री के कक्ष में होगी।

12. उपरोक्त नामित सभी वकील बिना किसी सूचना के उक्त बैठक में भाग लेंगे।

13. इसे 16 मई, 2008 को उसी शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करें।

इस आदेश की 35 प्रतियां तैयार की जाएं, जिनमें से 30 प्रतियां श्री मुखर्जी को सौंपी जाएं ताकि वे इसे विभिन्न बार संघों के वकीलों को आवश्यक वस्तुओं के लिए भेज सकें और 5 प्रतियां विद्वान महाधिवक्ता को सौंपी जाएं।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।